PK टाइम्स

दैनिक **लोक टुडे**
जनता की आवाज...
विश्वसनीय खबरों का सर्वश्रेष्ठ अखबार

pktimesnews.com
loktodaynews.com
PK Times News
thepktimesofficial
pk_timesofficial

वर्ष: 12 अंक: 333 | मूल्य: 1.00 रुपए | पृष्ठ: 4 | गुरुवार 18 जून 2026 | RNI No. RAJHIN/2013/50649

धुंध बनी काल, वडोदरा में दृश्यता कम होने से हुआ हादसा

वडोदरा में सड़क हादसा: राजस्थान के 7 लोगों की मौत, खड़े ट्रक में घुसी स्लीपर बस

कटिंग मशीनों की सहायता से बस में फंसे यात्रियों को निकाला बाहर

लोक टुडे। जयपुर

गुजरात के वडोदरा शहर में बुधवार तड़के हुए सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 27 यात्री घायल हो गए। मरने वाले सभी लोग डूंगरपुर और बांसवाड़ा के रहने वाले थे। बांसवाड़ा से सूरत (गुजरात) जा रही बालाजी ट्रैवल्स की स्लीपर बस कोटंबी स्टेडियम (वडोदरा) के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे के समय अधिकांश यात्री गहरी नींद में थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

जानकारी के अनुसार दुर्घटना सुबह करीब 4 बजे हुई। एक्सीडेंट के बाद बस में चीख-पुकार मच गई। कई यात्री बस के अंदर फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और वडोदरा अग्निशमन विभाग की टीमें पहुंचीं। जानकारी के मुताबिक सुबह 4:40 बजे कंट्रोल रूम को दुर्घटना की सूचना मिली। टीम ने आधुनिक उपकरणों और कटिंग मशीनों की सहायता से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे की सूचना मिलते ही बस में सफर कर रहे यात्रियों के परिजनों में चिंता बढ़ गई। कई परिवार फोन और अन्य माध्यमों से अपने रिश्तेदारों की जानकारी जुटाने में लगे रहे।

डूंगरपुर-बांसवाड़ा के सभी मृतक -

डूंगरपुर जिले के पाडवा की रहने वाली पिंकी भाटिया (36), डूंगरपुर के टामटिया की रहने वाले प्रीत (9) पुत्री हितेश भाटिया, डूंगरपुर निवासी- महेंद्र कुमार (68) पुत्र भोगीलाल पांडया (68), डूंगरपुर के सागवाड़ा निवासी विनोद (30) पुत्र नरेश डामोर और ड्राइवर डूंगरपुर के राजवाड़ा निवासी ड्राइवर मुकेश (34) पुत्र जीवाजी डिंडोर की मौत हो गई है। इसके अलावा मृतकों में हरजिंगभाई वलजीभाई कटारा (30) और एक अज्ञात व्यक्ति शामिल है।

दो दर्जन से अधिक हुए घायल

घायलों में पायल नाई, पिंकी रावल, मनीषा रावल, रामचंद्र डोरिया, शिल्पा पाटीदार, महेंद्र कटारा, आशीष यादव, आशीष कटारा, बंसीलाल राणे, जीवराजभाई, गुंजनबेन, नाराचया, पिंटू चरपोट, विजय कटारा, भेरूलाल मीना, सीमा यादव, सागर कटारा, भगवती भाई, कल्पेश गौर, पैलबेन नाई, शील, सुरेशभाई डिंडोर, रमेशभाई, पंकजभाई चरपोट, कमलेशभाई कटारा, मायाबेन पाटीदार सहित अन्य यात्री शामिल हैं। इसके अलावा 2 की हालत गंभीर है। उन्हें आईसीयू में भर्ती किया है। डॉक्टरों ओर नर्सिंगकर्मियों की टीम अलर्ट मोड में हैं।

हादसे के कारणों की जांच जारी -

फिलहाल दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रारंभिक तौर पर तेज रफ्तार या ड्राइवर की लापरवाही को हादसे की वजह माना जा रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। दुर्घटना के बाद कुछ समय के लिए ट्रैफिक जाम हो गया। बाद में ट्रक और क्षतिग्रस्त बस को हटाकर यातायात सुचारु कर लिया गया था।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि अर्पित कर किया नमन

जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाराणा प्रताप जंयती (ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया) के अवसर पर बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर उनके छात्राचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया।
उन्होंने कहा कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप स्वाभिमान, समर्पण और राष्ट्र चेतना के शाश्वत प्रतीक है। उनका त्याग, शौर्य एवं पराक्रम युगों-युगों तक राष्ट्र को प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे सभी महाराणा प्रताप के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करें और समाज एवं देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भागीरथ चौधरी , विधानसभा अध्यक्ष वासूदेव देवनानी भी मौजूद रहे।

जयपुर में 450 किलो पनीर नाली में फिकवाया

अलवर से 220 रुपए किलोग्राम में खरीदता था डेयरी का मालिक

एजेंसी

जयपुर (का.सं.)। जयपुर सीएमएचओ (सेकंड) की टीम ने मंगलवार को खो-नागोरियान क्षेत्र में 450 किलो पनीर नष्ट करवाया। टीम को आशंका थी कि ये पनीर स्टैण्डर्ड के मुताबिक नहीं है। वहीं, पनीर में से बदबू भी आ रही थी। इसके चलते पनीर का सैंपल लेने के बाद उसे नष्ट करवाया।

सीएमएचओ डॉ. मनीष मित्तल ने बताया- पुलिस थाना खो नागोरियान की सूचना पर टीम को लक्ष्मी नगर स्थित एम.के. डेयरी पर भेजा। यहां टीम ने डीप फ्रिज और कैरटों रखा करीब 450 किलो पनीर चैक किया।

डेयरी के मालिक मुस्तफा ने पूछताछ में बताया- वह ये पनीर अलवर से 220 रुपए किलो की दर से मंगवाता है। जयपुर के अलग-अलग बाजार में 260 रुपए किलो में बेचता है। यह पनीर दूध में से क्रीम निकालकर तैयार किया जाता है।

इस प्रकार क्रीम निकालकर लूज पनीर तैयार कर बेचना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रतिबंधित है। पनीर की क्वालिटी घटिया होने और दूषित होने के साथ मिलावट का अंदेशा होने पर कारण पनीर का नमूना लेकर पूरे पनीर के स्टॉक (450 किलो पनीर) को टीम ने नष्ट करवाया।

एयरफोर्स अफसर की पत्नी से रेप धर्म परिवर्तन की कोशिश भी हुई

एजेंसी

नागपुर (एजेंसी)। नागपुर में भारतीय वायुसेना के एक अफसर की 24 साल की पत्नी से रेप, ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्मांतरण के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले का मुख्य आरोपी अयाज ताज मदारे पीड़ित के साथ स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ता था।

एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी अयाज महिला के हाथ पकड़कर कुछ पढ़ रहा है। महिला कहती है, 'तुम्हें लड़ने की बहुत आदत है ना, हाथ छोड़ो ना... छोड़ो।' इसके बाद वह लगातार 'मुझे छोड़ दो' कहकर रोती और विरोध करती है, लेकिन आरोपी जोर से उसके हाथ पकड़े रहता है। पीड़ित के मुताबिक, घटना सालभर पुरानी है। आरोपी उस पर कुछ शब्द पढ़कर फूंकता था, इसके बाद उसका रेप करता था। महिला की शिकायत पर सोनेगांव पुलिस ने स्नद्धत्र दर्ज करके दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले का रहने वाला एक आरोपी मौलाना फरार है। पुलिस के मुताबिक, पीड़ित के पति भारतीय वायुसेना में हैं और फिलहाल दूसरे शहर में पोस्टेड है। महिला प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करती है। फरवरी 2025 में आरोपी अयाज ने प्लॉट खरीदने के बहाने उससे संपर्क किया था। स्नद्धत्र के मुताबिक, आरोपी ने महिला को वर्धा रोड स्थित एक होटल में बुलाया। महिला का आरोप है कि वहां उसे नशीला पदार्थ मिला जूस पिलाया गया। बेहोशी की हालत में उसके साथ रेप किया गया और उसकी फोटो-वीडियो बना ली गईं।

बाद में इन्हीं आपत्तिजनक वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल किया गया। आरोपी ने कई बार उसका यौन शोषण किया और उससे करीब 4 लाख रुपए भी वसूले। महिला ने आरोप लगाया कि उस पर इस्लाम अपनाने का दबाव बनाया गया और धार्मिक रस्मों के नाम पर कई गतिविधियां कराई गईं।

सैटेलाइट इमेज में गायब दिखे मानसूनी बादल, अरब सागर में भी 8 जून से फंसा मानसून

राजस्थान में धूल का गुबार, एमपी में आंधी-बारिश: 6 दिन से तेलंगाना में अटका मानसून, उत्तर भारत में बारिश का इंतजार बढ़ा

एजेंसी

भोपाल / जयपर / लखनऊ / पटना । राजस्थान में मंगलवार को राजस्थान में प्री-मानसून सीजन शुरू हो गया है। मंगलवार को सीकर, बीकानेर में बारिश हुई। श्रीगंगानगर-चूरू में धूल का गुबार छा गया। इधर, मध्य प्रदेश में मंगलवार को भी आंधी-बारिश का दौर जारी रही। सीधी, बैतूल, रीवा-सतना में तेज बारिश हुई।

मानसून तेलंगाना के भद्राचलम में 6 दिन से अटका हुआ है। इस वजह से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बारिश में देरी हो गई है। यहां कई हिस्सों में गर्मी लौट आई है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गनाइजेशन की हाइड्रोमेट्री टीम के मेंबर डॉ. पंकज कुमार के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 3 से 4 दिन, तो मध्य प्रदेश-यूपी में मानसून की एंट्री हफ्तेभर बाद हो सकती है। उनका यह भी कहना है कि इस हफ्ते के अंत तक बारिश में सुधार संभव है। मानसून के कमजोर होने की वजह समुद्र में

नमी की कमी नहीं, बल्कि करीब 15 किमी. ऊपर बह रही हवाओं का असामान्य पैटर्न है। इन हवाओं को जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये इस बार सामान्य से ज्यादा दक्षिण की ओर खिसक गई है, जिससे मानसून की गति प्रभावित हो रही है।

अरब सागर में भी 8 जून से फंसा मानसून: इधर, अरब सागर से उठ रही मानसूनी हवाएं भी 8 जून से अटकी हुई हैं। इस वजह से देश के अंदर पहुंच चुकीं मानसूनी हवाओं को पुश नहीं मिल पा रहा है। यानी, मानसूनी हवाओं को तेलंगाना से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरफ धकेलने के लिए जरूरी प्रेशर नहीं बन रहा है।

सैटेलाइट इमेज में गायब दिखे मानसूनी बादल: 15 जून की सैटेलाइट तस्वीरों में देश के बड़े हिस्से से मानसूनी बादल गायब दिखाई दिए। एक दिन पहले, यानी 14 जून को भारत का बड़ा हिस्सा बादलों से ढका दिखाई दिया था। मौसम विभाग के मुताबिक, 4 जून से 15 जून के बीच देश में सामान्य 53.7 मिमी के मुकाबले सिर्फ 19.2 मिमी बारिश हुई। यानी बारिश में 64% की कमी दर्ज की गई है।

राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई शहरों में सोमवार को तापमान 40डिग्री से ज्यादा रहा। देश में सबसे ज्यादा पारा 43.4डिग्री उत्तर प्रदेश के बांदा में दर्ज किया गया।

वहीं एमपी के खजुराहो 42.6डिग्री, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 42डिग्री, ओडिशा के बौध में 42.5डिग्री, महाराष्ट्र के वर्धा में 41.5डिग्री, बिहार के शेखपुरा में 41.5डिग्री, राजस्थान के फलोदी में 42.8डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक, जेट स्ट्रीम का मौजूदा पैटर्न कमजोर होने पर मानसूनी हवाएं तेज होंगी। अगले 4-5 दिनों में मानसून के महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और अन्य हिस्सों में आगे बढ़ने की परिस्थितियां बन सकती हैं।

जेट स्ट्रीम वायुमंडल की ऊपरी परतों में बहने वाली अत्यंत तेज हवाएं हैं। ये आमतौर पर पृथ्वी की सतह से करीब 8 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। ये मानसूनी बादलों और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ को प्रभावित करती हैं।

अगले दो दिन के मौसम का हाल

17 जून: बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश की संभावना। बिहार में कुछ जगहों पर 50-70 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। कई इलाकों में 40-60 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।

18 जून: सिक्किम, उत्तर बंगाल, असम और मेघालय में भारी बारिश की संभावना है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बारिश के साथ 40-60झ्द्रश्चद्ध की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बारिश जारी रह सकती है।

ट्रम्प बोले-ईरान को 28 लाख रुपए करोड़ देने की बात फर्जी, यह झूठ विपक्ष ने फैलाया

नेतन्याहू पर कहा- मैं न होता, तो इजराइल नहीं होता

एजेंसी

तेल अवीव / तेहरान / वॉशिंगटन डीसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को 28 लाख करोड़ रुपए देने की बात को फर्जी बताया है। उन्होंने मंगलवार को ट्रुथ सोशल पर लिखा कि यह विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट्स की तरफ से फैलाई गई झूठी खबर है।

दरअसल, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि समझौता होने पर अमेरिका, ईरान को आर्थिक मदद के तौर पर करीब 28 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगा। वहीं, ट्रम्प ने फ्रांस में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी से मुलाकात में भी बताया कि अमेरिका अभी ईरान में कोई पैसा नहीं लगा रहा है। साथ ही, ट्रम्प ने इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेबनान मुद्दे पर ज्यादा जिम्मेदारी दिखाने की सलाह दी है। ट्रम्प ने कहा, 'मैं न होता, तो इजराइल नहीं होता। किसी दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल के लिए उतना

नहीं किया, जितना मैंने किया है'।

ट्रम्प बोले- ईरान शर्तें पूरी करे तभी राहत मिलेगी: अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ किया कि ईरान को प्रतिबंधों से राहत तभी मिलेगी, जब वह समझौते की सभी शर्तों का पालन करेगा। अमेरिका ने फिलहाल किसी भी तत्काल आर्थिक राहत से इनकार किया है।

दुनियाभर के देशों ने समझौते का स्वागत किया: यूएई, कुवैत, स्विट्जरलैंड, कतर और पाकिस्तान समेत कई देशों ने अमेरिका-ईरान समझौते को क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की दिशा में बड़ा कदम बताया है।

मैक्रों ने यूरेनियम पर शर्त रखी: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार को निष्क्रिय कर द्बश्व की निगरानी में रखा जाना चाहिए, ताकि उसका इस्तेमाल परमाणु हथियारों के लिए न हो सके।

इजराइल ने डील से किनारा किया: इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ग्वीर ने कहा कि यह ट्रम्प की डील है और इजराइल इससे बंधा नहीं है। वहीं रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने भी साफ किया कि दक्षिणी लेबनान से सेना नहीं हटेगी।

ईरान-ओमान बोले- हॉर्मुज में सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेंगे

ईरान और ओमान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने का भरोसा दिया है। दोनों देशों ने कहा कि वे इस अहम समुद्री मार्ग को लेकर अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची और ओमान के विदेश मंत्री बद्र बिन हमद अल-बुसैदी ने फोन पर बातचीत में हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़े अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

ईरान ने समझौते को अपनी जीत बताया: ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजशकियान ने अमेरिका के साथ हुए समझौते को 'जीत का दस्तावेज' बताया। उन्होंने कहा कि इजराइल की नाराजगी ही साबित करती है कि बातचीत में ईरान मजबूत स्थिति में रहा।

अवैध पटाखा फैक्ट्री में काम करने वाले जिंदा जल गए थे, 2 आरोपी अब भी फरार

जयपुर में 8 लोगों की मौत का जिम्मेदार गिरफ्तार

एजेंसी

जयपुर । जयपुर के खोह नागोरियान इलाके में अवैध पटाखा फैक्ट्री में 9 जून को हुए अग्निकांड के मुख्य आरोपी कयूम खान (50) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा अभी 2 अन्य मुख्य आरोपी फरार हैं। इनमें कयूम का भाई याकूब और इनका बिजनेस पार्टनर फिरोज शामिल हैं।

पुलिस टीम ने मंगलवार को अलीगढ़ (यूपी) में दबिश देकर उसे दबोचा। वह पिछले एक हफ्ते से दिल्ली और ब्क में अपने ठिकाने बदल-बदलकर फरारी काट रहा था। डीसीपी (ईस्ट) रंजिता शर्मा ने बताया- कयूम खान राक्ष्या की ढाणी, खोह-नागोरियान, जयपुर का रहने वाला है। उसकी तलाश में पुलिस की टीमें पिछले 8 दिनों से दिल्ली और उत्तर प्रदेश (यूपी) में लगातार छापेमारी कर रही थीं। पूछताछ में सामने आया है कि फरारी के दौरान कयूम ने पकड़े जाने के डर से अपने रिश्तेदारों और परिजनों से भी संपर्क पूरी तरह

दिल्ली से जयपुर तक फैला था नेटवर्क

पुलिस जांच में सामने आया कि कयूम खान ने ज्यादा पैसे कमाने के लालच में पार्टनरशिप में यह अवैध पटाखा फैक्ट्री खोली थी। जयपुर के रहीम नगर सेकेंड स्थित उसका आलीशान मकान है। यहीं से यह पूरे नेटवर्क को ऑपरेट करता था। कयूम के साथ उसका भाई याकूब भी इसी आलीशन घर में रहता है। दोनों भाई मिलकर इस अवैध फैक्ट्री को ऑपरेट कर रहे थे। कयूम दिल्ली से शुरू हुए इस अवैध कारोबार को जयपुर में बड़े स्तर पर फैलाने की तैयारी में था।

जी-7 शिखर सम्मेलन में अमेरिका दिखा अलग थलग, दुनिया जता रही मोदी पर भरोसा

नीरज कुमार दुबे

ईरान युद्ध के बाद पैदा हुई वैश्विक बेचैनी ने इस सम्मेलन को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। युद्धविराम की घोषणा के बावजूद तेल बाजारों में अस्थिरता बनी हुई है, महंगाई को लेकर चिंता गहरा रही है और दुनिया की अर्थव्यवस्था फिर अनिश्चितता के मोड में पहुंचती दिखाई दे रही है।

जी-7 शिखर सम्मेलन इस बार वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और व्यापार का मंच नहीं बल्कि बदलती विश्व व्यवस्था का आईना प्रतीत हुआ। फ्रांस में आयोजित इस सम्मेलन में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे तो उनके सामने वह यूरोप खड़ा था जो अब आंख मूंदकर वॉशिंगटन के पीछे चलने को तैयार नहीं दिखता। लंबे समय तक टैरिफ की धमकियां, कूटनीतिक दबाव, सार्वजनिक अपमान और अचानक फैसलों का सामना करने के बाद अब यूरोपीय देशों ने यह मान लिया है कि ट्रंप बदलती अमेरिकी सोच का स्थायी चेहरा हैं। यही कारण है कि इस बार जी-7 सम्मेलन पर सबसे गहरी छाया अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ती दूरी की रही।

देखा जाये तो ईरान युद्ध के बाद पैदा हुई वैश्विक बेचैनी ने इस सम्मेलन को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। युद्धविराम की घोषणा के बावजूद तेल बाजारों में अस्थिरता बनी हुई है, महंगाई को लेकर चिंता गहरा रही है और दुनिया की अर्थव्यवस्था फिर अनिश्चितता के मोड में पहुंचती दिखाई दे रही है। ट्रंप इस सम्मेलन में यह साबित करने पहुंचे कि उनकी आक्रामक और टकराव वाली विदेश नीति परिणाम दे रही है। वह चाहते हैं कि दुनिया अमेरिकी प्राथमिकताओं को स्वीकार करे, चाहे मामला व्यापार का हो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का, सुरक्षा का या फिर चीन को घेरने की रणनीति का। लेकिन इस बार यूरोप का स्वर बदला हुआ है। वह अमेरिका के साथ तो रहना चाहता है, मगर उसकी हर बात पर सिर झुकाने को तैयार नहीं है।

देखा जाये तो यूरोप के भीतर यह बदलाव अचानक नहीं आया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों वर्षों से यूरोप की रणनीतिक स्वायत्तता की वकालत करते रहे हैं। उनका तर्क साफ है कि यूरोप को अपनी सुरक्षा और अपने हितों की रक्षा के लिए हमेशा अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इस बार सम्मेलन की मेजबानी कर रहे मैक्रों ने साफ शब्दों में कह दिया है कि यह ऐसा समय है जब अमेरिकी, रूसी और चीनी नेतृत्व यूरोप के हितों के खिलाफ खड़ा दिखाई देता है। इसलिए यूरोप को अब जागना होगा और अपने हितों की रक्षा खुद करनी होगी।

हालांकि मैक्रों की रणनीति केवल विरोध की नहीं है। उन्होंने ट्रंप के साथ निजी संबंध बनाए रखने की भी भरपूर कोशिश की है। कभी एफिल टावर पर भोज, कभी सैन्य परेड में विशेष सम्मान और कभी नोट्रे डेम कैथेड्रल के पुनरोद्धार समारोह में आमंत्रण देकर उन्होंने ट्रंप को साधने की कोशिश की है। लेकिन ईरान युद्ध और ग्रीनलैंड विवाद के बाद यूरोप में ट्रंप विरोध चरम पर पहुंच गया। एक समय तो हालात ऐसे बन गए थे कि यूरोपीय नेताओं को लगने लगा कि ट्रंप

डेनमार्क के अधीन ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए अमेरिकी सेना भेज सकते हैं। यह केवल एक भू-राजनीतिक विवाद नहीं था, बल्कि उस भरोसे के टूटने का प्रतीक था जिस पर दशकों से अटलांटिक गठबंधन टिका हुआ था।

दरअसल, ग्रीनलैंड प्रकरण ने यूरोप को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं नाटो की सबसे बड़ी सैन्य ताकत ही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा न बन जाए। यही कारण है कि अब यूरोपीय देशों में यह बहस तेज हो गई है कि अगर अमेरिका हर वैश्विक संकट में नेतृत्व नहीं करता या करना नहीं चाहता, तो आगे की दुनिया कैसी होगी। इस चिंता ने नाटो और अटलांटिक गठबंधन की नींव तक को हिला दिया है।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भी इस बार दबाव में दिखे। घरेलू राजनीति में चुनौती झेल रहे स्टारमर को ईरान पर अमेरिकी हमलों का समर्थन न करने के कारण ट्रंप की नाराजगी का सामना करना पड़ा। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से ब्रिटेन का मजाक उड़ाया और उसे असहयोगी तक कह दिया। नतीजा यह हुआ कि ब्रेक्जिट के बाद अमेरिका के और करीब जाने की कोशिश कर रहा ब्रिटेन अब फिर यूरोप की ओर झुकता दिखाई दे रहा है।

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जिन्हें कभी ट्रंप का स्वाभाविक सहयोगी माना जाता था, वह भी अब दूरी बनाती नजर आ रही हैं। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची इस सम्मेलन में पहली बार शामिल हुईं और उन्होंने अमेरिका, यूरोप तथा पश्चिम एशिया के बीच संवाद की कड़ी बनने की कोशिश की। साफ है कि दुनिया अब केवल अमेरिकी नेतृत्व पर निर्भर रहने की बजाय बहुध्रुवीय संतुलन की तरफ बढ़ रही है।

देखा जाये तो ट्रंप की सबसे बड़ी चुनौती यह भी है कि वह निजी कूटनीति को सार्वजनिक तमाशे में बदल देते हैं। पिछले वर्ष नाटो प्रमुख मार्क रुटे के निजी संदेश सार्वजनिक कर उन्होंने यह दिखा दिया था कि यूरोपीय नेता निजी तौर पर अमेरिका के दबाव को स्वीकार करते हैं, भले ही सार्वजनिक मंचों पर विरोध का अभिनय करें। इस कारण अब यूरोपीय नेताओं के लिए संतुलन साधना और मुश्किल हो गया है। उन्हें अपने मतदाताओं को भी संतुष्ट रखना है और अमेरिका से रिश्ते भी नहीं बिगाड़ने हैं।

इसी उथल पुथल के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी इस सम्मेलन में विशेष महत्व रखती है। जब पश्चिमी दुनिया भीतर से विभाजित दिखाई दे रही है, तब भारत एक ऐसे संतुलित और भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभरा है जिस पर हर शक्ति केंद्र भरोसा करना चाहता है। मोदी ने रूस और अमेरिका दोनों से संबंध बनाए रखे, पश्चिम एशिया के संकटों में संतुलन साधा और ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। यही वजह है कि आज दुनिया भारत को केवल एक बाजार नहीं, बल्कि स्थिर नेतृत्व वाली निर्णायक शक्ति के रूप में देख रही है।

देखा जाये तो मोदी की कूटनीति की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उन्होंने भारत को किसी एक खेमे में सीमित नहीं होने दिया। अमेरिका से रणनीतिक साझेदारी भी कायम रखी और रूस के साथ पुराने रिश्ते भी नहीं टूटने दिए। पश्चिम एशिया में भारत की स्वीकार्यता बनी रही और यूरोप के साथ आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग भी लगातार बढ़ता गया। जी-7 जैसे मंचों पर मोदी की उपस्थिति इस बात का संकेत है कि बदलती विश्व व्यवस्था में भारत केंद्र में आ चुका है। जब दुनिया अविश्वास, टकराव और अनिश्चितता से जूझ रही है, तब भारत संवाद, संतुलन और स्थिरता का चेहरा बनकर उभरा है। यही प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है।

बहरहाल, जी-7 शिखर सम्मेलन 2026 की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि गहरे मतभेदों और पश्चिमी देशों के भीतर बढ़ती अविश्वास की राजनीति के बावजूद संवाद की प्रक्रिया टूटी नहीं। ईरान संकट के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था में पैदा हुए तनाव, तेल आपूर्ति को लेकर आशंकाओं और यूक्रेन युद्ध की लंबी खिंचती स्थिति के बीच सदस्य देशों ने कम से कम इस बात पर सहमति दिखाई कि बहुपक्षीय सहयोग को जिंदा रखना जरूरी है। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वैश्विक आर्थिक असंतुलन, आपूर्ति श्रृंखला, महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षा और विकासशील देशों के कर्ज संकट जैसे मुद्दों पर साझा चर्चा आगे बढ़ी। यूरोप ने अपनी सामरिक स्वायत्तता का स्वर बुलंद किया, जबकि अमेरिका ने भी यह संकेत दिया कि यूरोपीय देशों को अपनी सुरक्षा जिम्मेदारियों में अधिक भागीदारी निभानी होगी। भारत, ब्राजील, केन्या और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की भागीदारी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि ग्लोबल साउथ को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकासशील देशों की आकांक्षाओं को मजबूती से उठाकर भारत की वैश्विक भूमिका को और मजबूत किया।

हालांकि सम्मेलन कई अहम मुद्दों पर ठोस नतीजे देने में विफल भी रहा। यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई निर्णायक रोडमैप सामने नहीं आया, चीन को लेकर पश्चिमी देशों के भीतर मतभेद बने रहे और जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर विषय को जानबूझकर पीछे कर दिया गया ताकि अमेरिका और यूरोप के बीच टकराव नहीं बढ़े। ईरान समझौते पर भी स्पष्टता का अभाव रहा और ट्रंप की आक्रामक शैली के कारण साझा घोषणापत्र को लेकर एकजुटता कमजोर दिखाई दी। कुल मिलाकर यह सम्मेलन उपलब्धियों से अधिक बदलती विश्व राजनीति के अंतर्विरोधों का प्रतीक बनकर सामने आया, जहां संवाद तो जारी रहा लेकिन भरोसे का संकट अब भी गहराता दिखाई दिया।

संपादकीय

'चिट्टा' को चुनौती

हाल के दिनों में पंजाब के बाद, हिमाचल के लिए भी नशीले पदार्थों का तेजी से बढ़ता दुरुपयोग एक गंभीर सामाजिक चुनौती बन गया है। नशे के बढ़ते सेवन की जो समस्या कभी सीमावर्ती राज्यों व सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक सीमित मानी जाती थी, अब दुर्भाग्य से वह इस पहाड़ी राज्य के गांवों तक पहुंच गई है। जिससे कई परिवारों का अस्तित्व, लोगों की आजीविका और युवा पीढ़ी का भविष्य भी खतरे में नजर आ रहा है। ऐसे हालात में राज्य सरकार का वह फैसला एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया है, जिसमें नशीले पदार्थों से मुक्ति के अभियान ह्यचिट्टा-मुक्त गांवह्ण में पंचायतों को शामिल करने का रणनीतिक निर्णय लिया गया है। सालों तक इस संकट को कानून व्यवस्था से जुड़ा प्रश्न माना जाता रहा है। नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने के लिये सप्लायरों व नशे की आदत का शिकार लोगों की गिरफ्तारी, नशीले पदार्थों की बरामदगी और पुलिस की कार्रवाई को प्राथमिकता बना लिया गया था। निस्संदेह, कानून के अनुपालन के बिना इस संकट का समाधान संभव भी नहीं था, लेकिन सिर्फ इन प्रयासों से सफलता कम ही मिली। नशीले पदार्थ बेचने वालों की गिरफ्तारी के बाद सप्लाई चेन तेजी से बदल जाती है। नशे के कारोबारी स्थानीय तंत्र की कमजोरी का लाभ उठाते और नये लोग नशे की लत की चपेट में आ जाते थे। इस संकट के बने रहने ने संकेत दिए कि यह समस्या सिर्फ कानूनी नहीं है बल्कि इसे एक सामाजिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े संकट के रूप में भी देखा जाना चाहिए। निर्विवाद रूप से किसी ग्रामीण समाज में पंचायतों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पंचायतें ग्रामीण परिवेश में स्थानीय हालात को बेहतर ढंग से समझती हैं। वहीं दूसरी ओर उन्हें स्थानीय समुदायों का विश्वास भी हासिल होता है। वे गांव के लोगों के व्यवहार संबंधी बदलावों को आसानी से से पहचान सकती हैं। ऐसे बदलाव जिन्हें दूर बैठे प्रशासन व पुलिस के अधिकारी नहीं समझ सकते। इस बात में दो राय नहीं हो सकती कि यदि पंचायतों को प्रभावी अधिकार और संसाधन उपलब्ध करा दिए जाएं तो वे जागरूकता अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं। साथ ही ग्रामीण परिवारों को समय रहते मदद लेने को प्रोत्साहित कर सकती हैं। इतना ही नहीं, वे इस जागरूकता अभियान का दायरा बढ़ाने और बेहतर परिणाम हासिल करने के लिये स्कूल तथा स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सार्थक तालमेल स्थापित कर सकती हैं। साथ ही बिना किसी भेदभाव के, संवेदनशील ढंग से पुनर्वास के प्रयासों में मदद कर सकती हैं। वहीं दूसरी ओर गांव स्तर पर निगरानी समितियां बनाकर पंचायतें नशे की आपूर्ति श्रृंखला पर नजर रख सकती हैं। वे समय रहते कानून के क्रियान्वयन करने वाली एजेंसियों को भी सतर्क करने में मददगार साबित हो सकती हैं।

चिंतन-मनन

संत की उदारता

विख्यात संत एकनाथ जी 12 वर्ष की अवस्था में ही अपने गुरु जनार्दन स्वामी के पास देवगढ़ पहुंच गए थे। गुरु ने उन्हें आश्रम के हिसाब-किताब का काम सौंप दिया। एक दिन जब एकनाथ जी ने हिसाब और रोकड़ का काम किया तो एक पाई की कमी नजर आई। खूब सोचने के बाद आखिरकार उन्हें आधी रात को एक पाई का हिसाब मिल गया तो उन्होंने उसी समय अपने गुरुजी को जाकर यह बात बताई। इस पर गुरु हंसे फिर बोले- बेटा! एक पाई की भूल मिलने से तुम इतने प्रसन्न हो और इस संसार के मायाजाल जैसी महाभूल को अपनाए हुए हो। इस पर कभी सोचा है?

यह सुनते ही एकनाथ जी के भीतर वैराग्य जागा और दुनिया के कामकाज से उनका मोहभंग हो गया। उन्होंने उसी समय सब कुछ छोड़ देने का फैसला किया। वे अपने गुरु से दीक्षा लेकर पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। तपस्या के बाद वे अपनी जन्मभूमि के निकट पिपलेश्वर महादेव में रहने लगे। पर थोड़े ही समय बाद वे विवाह कर गृह संन्यासी बन गए। एकनाथ जी ने गुरू के आदेश का पालन किया। विवाह के बाद उनके घर में नित्य कीर्तन होता और अन्न वितरण किया जाता। एक दिन कीर्तन में कुछ चोर आ गए। उन्होंने घर का सभी सामान समेट लिया। फिर उन्होंने देवमूर्ति के आभूषण चुराने का प्रयास किया। वहीं एकनाथ जी ध्यानमग्न बैठे थे। उन्होंने चोरों से कहा- तुम्हें इनकी बहुत अधिक आवश्यकता होगी अन्यथा इतनी रात गए भला कोई जोखिम क्यों उठाता? तुम सब मुसीबत के मारे लगते हो। चिंता मत करो। मुझसे जो मदद होगी, मैं करूंगा। यह कहते हुए उन्होंने अपनी उंगली की अंगूठी भी उतार कर उन्हें दे दी। यह देख चोर लज्जित हुए। वे एकनाथ जी के चरणों में गिर गए और उन्होंने कभी चोरी न करने का संकल्प लिया।

ललित गर्ग

चिन्ताजनक है महंगी होती दवाइयां, महंगा होता इलाज

भारत आज विकसित राष्ट्र बनने के स्वप्न के साथ आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की परिकल्पना बार-बार दोहराई जा रही है। बड़े-बड़े बुनियादी ढांचे, डिजिटल क्रांति, अंतरिक्ष उपलब्धियां और आर्थिक विकास के दावों के बीच एक प्रश्न बार-बार सामने खड़ा हो जाता है-क्या ऐसा भारत वास्तव में विकसित कहलाएगा, जहां एक सामान्य नागरिक बीमारी के कारण कर्ज में डूबने को विवश हो जाए? जहां इलाज और दवाइयों की बढ़ती कीमतें जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी तय करने लगें? जहां स्वास्थ्य सेवा अधिकार नहीं, बल्कि आर्थिक सामर्थ्य का विषय बन जाए? ऐसे समय में जब महंगाई पहले ही आम आदमी की कमर तोड़ रही है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एन.पी.पी.ए.) द्वारा कुछ जीवनरक्षक दवाओं और टीकों की कीमतों में भारी वृद्धि की अनुमति देना गंभीर चिंता का विषय है। कैंसर की कुछ दवाओं, एंटी-टेटनस सीरम और बच्चों के आवश्यक टीकों की कीमतों में लगभग पचास प्रतिशत तक वृद्धि की स्वीकृति ने लाखों परिवारों के सामने नया संकट खड़ा कर दिया है। यह निर्णय केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, मानवीय संवेदना और जनकल्याणकारी शासन की अवधारणा से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है।

भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति किसी से छिपी नहीं है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देश में बड़ी संख्या में लोग आज भी अपने इलाज का खर्च अपनी जेब से वहन करते हैं। बीमारी केवल स्वास्थ्य संकट नहीं रह जाती, वह आर्थिक संकट में भी बदल जाती है। एक समय था जब कहा जाता था कि व्यक्ति अपनी बेटी की शादी के कारण कर्ज में डूबता है, लेकिन आज की स्थिति यह है कि किसी गंभीर बीमारी का इलाज पूरा परिवार आर्थिक रूप से बर्बाद कर सकता है। कैंसर, हृदय रोग, किडनी रोग या अन्य जटिल बीमारियों का उपचार लाखों रुपये की मांग करता है। ऐसे में यदि जीवनरक्षक दवाइयों की कीमतें भी लगातार बढ़ती रहें तो गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लिए स्वास्थ्य सेवा लगभग असंभव हो जाएगी। एन.पी.पी.ए. ने दवाओं की कीमत बढ़ाने के पीछे उत्पादन लागत में वृद्धि और बाजार में संभावित कमी का तर्क दिया है। उनका कहना है कि यदि दवा कंपनियां लागत भी नहीं निकाल पाएंगी तो वे उत्पादन बंद कर सकती हैं, जिससे मरीजों को आवश्यक दवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। यह तर्क अपनी जगह सही हो सकता है। किसी भी उद्योग को जीवित रहने के लिए उचित लाभ आवश्यक है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या जीवनरक्षक दवाओं को सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं की तरह देखा जा सकता है? क्या स्वास्थ्य क्षेत्र में लाभ कमाने की सीमा और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन स्थापित नहीं किया जाना चाहिए?

स्वास्थ्य और शिक्षा किसी भी सभ्य समाज की दो मूलभूत आवश्यकताएं हैं। दुर्भाग्य से भारत में इन दोनों क्षेत्रों में व्यवसायीकरण का प्रभाव लगातार बढ़ता गया है। निजी अस्पतालों की बढ़ती फीस, महंगे परीक्षण, अनावश्यक जांचें, चिकित्सा उपकरणों का भारी खर्च और अब दवाइयों की बढ़ती कीमतें मिलकर आम नागरिक को असहाय बना रही हैं। चिकित्सा सेवा धीरे-धीरे सेवा के बजाय उद्योग में परिवर्तित होती दिखाई दे रही है। अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र कम और कॉरपोरेट प्रतिष्ठान अधिक प्रतीत होने लगे हैं। रोगी अब मरीज नहीं, बल्कि ग्राहक की तरह देखा जाने लगा है। यह स्थिति केवल आर्थिक असमानता को ही नहीं बढ़ाती, बल्कि सामाजिक विभाजन को भी गहरा करती है। आज भी देश में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मुख्यतः उन्हीं लोगों को उपलब्ध हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है। गरीब व्यक्ति सरकारी अस्पतालों की लंबी कतारों, सीमित संसाधनों और अपर्याप्त सुविधाओं के भरोसे है। अमीर व्यक्ति अत्याधुनिक अस्पतालों और महंगे उपचारों का लाभ उठा सकता है। क्या यही सामाजिक न्याय है? क्या यही वह भारत है जिसकी कल्पना स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेक जनहितकारी योजनाएं लागू हुई हैं। आयुष्मान भारत जैसी योजना ने लाखों लोगों को राहत भी प्रदान की है। जन औषधि केंद्रों की स्थापना ने सस्ती दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास किया है। लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य क्षेत्र में व्याप्त व्यापक विसंगतियां अभी भी बनी हुई हैं। यदि दवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती रहें और निजी स्वास्थ्य सेवाएं अनियंत्रित होती जाएं, तो इन योजनाओं का प्रभाव सीमित हो जाएगा। वास्तविक चुनौती यह है कि स्वास्थ्य को बाजार की शक्तियों के हवाले छोड़ने के बजाय उसे जनकल्याण के केंद्र में रखा जाए। सरकार का दायित्व केवल योजनाओं की घोषणा करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रत्येक नागरिक को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। जीवनरक्षक दवाओं की कीमतों पर विशेष नियंत्रण होना चाहिए। सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। दवा खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। आवश्यक दवाओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार विशेष सहायता और सब्सिडी भी दे सकती है, ताकि लागत बढ़ने का पूरा बोझ मरीजों पर न पड़े। इसके साथ ही स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का दायरा और व्यापक होना चाहिए। अनेक गरीब और निम्न मध्यमवर्गीय परिवार ऐसे हैं जो किसी भी बीमा सुरक्षा से वंचित हैं। गंभीर बीमारी की स्थिति में वे अपनी जीवनभर की जमा पूंजी गंवा देते हैं। स्वास्थ्य बीमा केवल अस्पताल में भर्ती होने तक सीमित न रहे, बल्कि आवश्यक दवाओं और दीर्घकालिक उपचार को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि सरकार समय-समय पर दवा कंपनियों की लागत संरचना और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्र समीक्षा कराए। यदि वास्तव में लागत बढ़ी है तो उसका प्रमाण सार्वजनिक होना चाहिए। पारदर्शिता से जनता का विश्वास भी बढ़ेगा और अनावश्यक मूल्यवृद्धि पर भी रोक लगेगी। स्वास्थ्य नीति का मूल उद्देश्य कंपनियों के लाभ और नागरिकों के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करना होना चाहिए।

वर्ष 2047 का विकसित भारत केवल ऊंची इमारतों, तेज रफ्तार सड़कों और बढ़ती जीडीपी से नहीं बनेगा। उसका वास्तविक मूल्यांकन इस आधार पर होगा कि वहां का सबसे गरीब नागरिक कितना सुरक्षित, शिक्षित और स्वस्थ है। यदि एक किसान, मजदूर, कर्मचारी या निम्न आय वर्ग का व्यक्ति बीमारी के समय सम्मानपूर्वक इलाज प्राप्त नहीं कर सकता, तो विकास के दावे अधूरे रह जाएंगे। आज आवश्यकता केवल दवाइयों की कीमतों पर बहस करने की नहीं, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था की समग्र समीक्षा करने की है। यह स्वीकार करना होगा कि स्वास्थ्य कोई विलासिता नहीं, बल्कि मौलिक मानवीय अधिकार है। जिस राष्ट्र में नागरिकों को स्वस्थ जीवन का अवसर नहीं मिलता, वहां विकास की चमक भी फीकी पड़ जाती है।

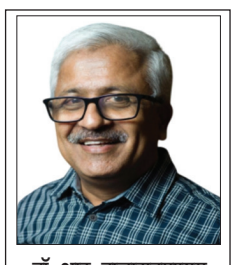

डॉ. आर. बालासुब्रमण्यम

वेतन से आगे: विकसित भारत के लिए कुशल कार्यबल की तैयारी

कोयंबटूर में काम करने वाले युवा रवि को, जो एक छोटी विनिर्माण इकाई में अपनी पहली औपचारिक नौकरी के छह महीने पूरे कर चुके हैं और हाल ही में अपनी मासिक तनख्वाह के अलावा उन्हें बैंक खाते में 7,500 रुपये मिले। लगातार छह महीने की नौकरी पूरी होने के बाद यह रकम अपने आप जारी कर दी गई। इससे पहले उनका परिवार सिर्फ. अनौपचारिक काम करता था, जिसमें कोई अनुबंध, भविष्य निधि में योगदान या नौकरी का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं होता था। यह पहला मौका था, जब उनकी नौकरी को आधिकारिक तौर पर दर्ज किया गया और उन्हें इस तरह का लाभ मिला। रवि को मिली यह धनराशि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) के 'भाग अ' के तहत मिली पहली किस्त है। इस योजना को केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री के रोजगार और कौशल पैकेज के हिस्से के तौर पर शुरू किया गया था। इस प्रावधान के तहत, ईपीएफओ में पंजीकृत कंपनियों में पहली बार नौकरी पाने वाले ऐसे कर्मचारी, जिनकी मासिक कमाई 1 लाख रुपये से कम है, उन्हें 15,000 रुपये तक का नकद प्रोत्साहन मिलता है। यह रकम दो किस्तों में दी जाती है: पहली किस्त लगातार छह महीने की नौकरी के बाद और दूसरी किस्त बारह महीने के बाद। इसके लिए शर्त यह है कि कर्मचारी को ईपीएफओ पोर्टल के जरिए वित्तीय साक्षरता का कोर्स पूरा करना होगा और यह राशि बचत के एक साधन में जमा की जाएगी, ताकि कर्मचारी को एक आर्थिक सुरक्षा मिल सके। रवि के लिए, ये छह महीने सिर्फ. योग्यता हासिल करने का समय नहीं थे। ये वो वक्त था, जिसमें उन्होंने अपने काम की जगह को समझा, अपने काम से जुड़ी बुनियादी कौशल और योग्यता सीखी और अपने लिए रोजगार का एक रिकॉर्ड बनाना शुरू किया, जो पहले कभी नहीं था। यह समय उनके नियोक्ता के लिए भी अहम था, जो एक छोटी विनिर्माण इकाई थी और उसने अपने विस्तार के तहत रवि को काम पर रखा था। पीएम-वीबीआरवाई के भाग इ में प्रावधान है कि जो नियोक्ता अपनी मौजूदा बेसलाइन से ज्यादा रोजगार पैदा करते हैं, उन्हें हर अतिरिक्त कर्मचारी के लिए हर महीने 3,000 रुपये तक का सरकारी योगदान मिलता है। यह योगदान अलग-अलग क्षेत्रों में दो साल तक और विनिर्माण क्षेत्र में चार साल तक मिलता है। यह योगदान उस शुरूआती लागत का कुछ हिस्सा कवर करता है, जो किसी कंपनी को नए कर्मचारी को रखने पर उठानी पड़ती है, खासकर तब जब ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण चल रहा होता है और बिना किसी पिछले औपचारिक अनुभव वाला कर्मचारी, धीरे-धीरे कंपनी के लिए लाभप्रद हो रहा होता है। इस शुरूआती लागत को कम करके यह प्रावधान, योजना का दायरा रवि जैसे लोगों को काम पर रखने वाले छोटे व्यवसायों तक बढ़ाता है। उसकी जैसी विनिर्माण इकाईयों के लिए, चार साल की अवधि, जो सामान्य अवधि से दोगुनी है, कंपनियों को ऑटोमेशन में निवेश के साथ-साथ अपने कार्यबल का विस्तार करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। भारत की जनसांख्यिकीय व्यवस्था को देखते हुए, युवा और बढ़ता कार्यबल 2047 तक 'विकसित भारत' की ओर बढ़ने के लिए रोजगार-आधारित विकास के जरिए आर्थिक विकास को रफ्तार देने का एक मौका देता है। कार्यबल में शामिल होने वाले नए लोग किस सीमा तक औपचारिक रोजगार में आते हैं, जहाँ उन्हें सामाजिक सुरक्षा और संस्थागत सुरक्षा मिलती है, यह इस बात पर भी असर डालेगा कि परिवारों और समुदायों में विकास का लाभ कैसे मिलता है। पीएम-वीबीआरवाई का मकसद 'स्वतंत्र भारत' से 'समृद्ध भारत' तक के सफर को मजबूत करना है और दो साल में 3.5 करोड़ से ज्यादा औपचारिक नौकरियाँ पैदा करने के लिए प्रोत्साहन देना है। इस योजना की शुरूआत से, 60 लाख नए कर्मचारी औपचारिक कार्यबल का हिस्सा बन चुके हैं। इनमें से 43.26 लाख (लगभग 71%) 18 से 30 साल की उम्र के हैं और 18.04 लाख (लगभग 30%) महिलाएं हैं, जो पहली बार औपचारिक रोजगार से जुड़ी हैं। ये कर्मचारी विशेष सेवाओं, इंजीनियरिंग, व्यापार, विनिर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, वस्त्र और आतिथ्य जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, जो दिखाता है कि कई तरह के औपचारिक संस्थानों में इसे अपनाया गया है। सिर्फ. प्रोत्साहन राशि के अलावा, पीएम-वीबीआरवाई से रवि को एक ईपीएफओ खाता और एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिला है। इससे वह एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा बन गए हैं, जो भविष्य निधि योगदान, बीमा सुरक्षा और कानूनी रोजगार लाभ भी देता है। उनके जैसे पहली बार औपचारिक रोजगार पाने वाले कई लोगों के लिए, यह सामाजिक सुरक्षा कवरेज और एक व्यवस्थित रोजगार से जुड़ने का एक बेहतर मौका है। लगातार छह महीने तक नौकरी करने की शर्त का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि इस योजना के तहत बनी नौकरियां असल करियर की नींव बनें। लंबे समय तक औपचारिक रोजगार से कई क्षेत्रों में नौकरियों में काम आने वाला कौशल विकसित होता हैं, पेशेवर तौर-तरीके सीखने को मिलते हैं और भविष्य में नौकरी पाने की क्षमता भी मजबूत होती है। इससे मिलने वाले फायदे योजना के तहत मिलने वाली मदद की अवधि के बाद भी बने रहते हैं। रोजगार के मौके पैदा करना एक अहम नीतिगत लक्ष्य है। उतना ही जरूरी यह सुनिश्चित करना भी है कि रवि जैसे कर्मचारी औपचारिक अर्थव्यवस्था में अपनी जगह बनाए रख सकें, जहाँ रोजगार के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा कवरेज और संस्थागत सुरक्षा भी मिलती है। जैसे-जैसे ज्यादा युवा कर्मचारी औपचारिक नौकरियों में छह महीने, एक साल और उससे ज्यादा समय बिताते हैं, कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आता है और छोटे संस्थान भी औपचारिक तरीके से लोगों को काम पर रखने की प्रक्रिया अपनाते हैं। इस योजना के तहत 3.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां मिलने का अनुमान है और औपचारिक अर्थव्यवस्था का यह धीरे-धीरे बढ़ता दायरा ही वह बदलाव है, जिसे तेजी से आगे बढ़ाने के लिए पीएम-वीबीआरवाई को लाया गया है।

(लेखक नीति आयोग के सदस्य हैं)

ईरान-यूएस डील पर सस्पेंस, एक-दो दिन में होर्मुज पूरी तरह खुलेगा

ट्रम्प बोले- अभी फाइनल नहीं, तेहरान ने शर्तें नहीं मानीं तो फिर बम बरसाएंगे

दोनों देशों के बीच फिलहाल सिर्फ एमओयू हुआ है और अभी कई बातें तय होना बाकी

● तेहरान/वॉशिंगटन

अमेरिका और ईरान के बीच डील पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि ईरान के साथ हुआ समझौता अभी फाइनल नहीं है। जी7 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल-सीसी से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच फिलहाल सिर्फ एमओयू हुआ है और अभी कई बातें तय होना बाकी हैं।

ट्रम्प ने चेतावनी दी कि अगर ईरान समझौते की शर्तों का पालन नहीं करता, तो यूएस फिर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने ठीक से व्यवहार नहीं किया, तो हम फिर बम बरसाएंगे। ट्रम्प ने यह भी दावा किया कि ईरान के साथ समझौते से बाजारों में भरोसा बढ़ा है और इसका असर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट अगले एक-दो दिन में पूरी तरह खुल जाएगा। उनके मुताबिक, समुद्री मार्ग पर जहाजों की आवाजाही धीरे-धीरे सामान्य हो रही है।

ट्रम्प बोले, बाजार बहुत खुश, तेजी आई

ट्रम्प ने दावा किया है कि अब इस बात की 99.99 फीसदी संभावना है कि ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा। उन्होंने यह बयान फ्रांस में जी-7 समिट के दौरान मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी के साथ मीडिया से बातचीत में दिया। ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत के बाद बाजारों में जबरदस्त तेजी आई है और तेल की कीमतें नीचे आई हैं। उन्होंने कहा कि बाजार बहुत खुश है। यही सबसे बड़ा संकेत है। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुआ समझौता क्षेत्र और दुनिया के लिए बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। फ्रांस के एवियन शहर में जी-7 नेताओं की बैठक के तीसरे दिन कार्नी ने पत्रकारों को बताया कि जी-7 देशों के नेताओं ने लेबनान की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा की। इस बैठक में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका के नेता शामिल थे। कार्नी के मुताबिक, मिडिल ईस्ट की मौजूदा परिस्थितियों और खासकर लेबनान की स्थिति पर नेताओं के बीच गहन चर्चा हुई।

अमेरिका और ईरान कल करेंगे स्विट्जरलैंड में एमओयू पर हस्ताक्षर

न्यूयॉर्क, (आरएनएन)। ब्लूमबर्ग ने अमेरिका और ईरान के बीच एक 14 सूत्रीय मसौदा ज्ञापन जारी किया है जिसके तहत दोनों पक्ष 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में एक एमओयू पर साइन होने हैं। मसौदे के अनुसार, इस एमओयू पर हस्ताक्षर होने के साथ ही ईरान-अमेरिका, वर्तमान युद्ध में शामिल अपने सहयोगियों के साथ लेबनान सहित सभी मोर्चों पर तत्काल और स्थायी रूप से युद्ध समाप्त करने की घोषणा करते हैं। इसके साथ ही वे अब एक-दूसरे के खिलाफ कोई भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई न करने का संकल्प लेते हैं। इसमें कहा गया है कि ईरान-यूएस एक-दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने तथा एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का संकल्प लेते हैं। मसौदे के मुताबिक, ईरान-यूएस वार्ता करने तथा अधिकतम 60 दिनों की अवधि के भीतर फाइनल डील पर पहुंचने की प्रतिबद्धता जताते हैं, जिसे आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है। इस एमओयू पर साइन होने के तुरंत बाद, यूएस नौसैनिक नाकेबंदी हटा लेगा।

अमेरिका ने हिंद-प्रशांत कमान का नाम बदला, इंडो शब्द को हटाया

भारत का गलत मैप दर्शाया, पीओके, अकसाई चीन को अलग किया

● वॉशिंगटन

यूएस ने अपने आठ साल पुराने फैसले को पलटते हुए अमेरिकी हिंद-प्रशांत कमान का नाम बदलकर फिर से अमेरिकी प्रशांत कमान (यूएसपीएकॉम) कर दिया है।

यूएस रक्षा मंत्रालय ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि यूएस प्रशांत कमान नाम 1947 में तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी एस. ट्रूमैन द्वारा स्थापित कमान की ऐतिहासिक जड़ों का सम्मान करता है। इसके अलावा, प्रशांत कमान की वेबसाइट पर मौजूद जिम्मेदारी वाले इलाके के मानचित्र ने देश में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं पैदा कर दी हैं। इसमें भारत की सीमाओं को सही रूप में नहीं दिखाया गया है। मानचित्र में, पीओके और अक्साई चिन को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया गया है। वेबसाइट के जिस हिस्से में गलत मानचित्र है, वहां यह जानकारी दी गई है कि संबंधित वेब पेज को आखिरी बार मार्च में अद्यतन किया गया था।

कांग्रेस ने किया पोस्ट

विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मानचित्र के मुद्दे पर भाजपा नीत केंद्र सरकार की आलोचना की है। कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मोदी जी के मित्रों की यह अजीब आदत रही है कि वे भारत, भारत के हितों और भारत के मित्रों के खिलाफ काम करते हैं। ताजा उदाहरण यह है कि यूएस पैसिफिक कमान ने भारत के गलत मानचित्र का इस्तेमाल किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर को भारत से अलग दिखाया गया है और पीओके को पाक का हिस्सा बताया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब एक पीएम ने देश को ऐसी शोषणकारी मित्रता के हवाले कर दिया हो तो फिर उस देश को दुश्मनों की क्या जरूरत है?

भारत के मेनाशे को इजराइल ले जाएगी

● नई दिल्ली

इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों मिजोरम और मणिपुर निवासी बेने मेनाशे समुदाय के सभी शेष सदस्यों को अगले चार वर्षों में इजराइल लाया जाएगा।

यह समुदाय यहूदी लोगों का अभिन्न हिस्सा है और इजराइल उनका घर है। हाल ही में इजराइल के नोफ हा-गलील शहर में बसे भारतीय मूल के यहूदी प्रवासियों को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मजबूत संबंधों के कारण दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ा है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत से अब तक समुदाय के करीब 600 सदस्य इजराइल पहुंच चुके हैं। वर्ष 2026 के अंत तक लगभग 600 और लोगों के आने की उम्मीद है। बेने मेनाशे का अर्थ है मनश्शे के पुत्र। यह समुदाय मुख्य रूप से मिजोरम और मणिपुर में रहता है। समुदाय के लोग सबाथ का पालन, यहूदी त्योहारों का आयोजन, कोषेर भोजन परंपरा और अन्य यहूदी रीति-रिवाजों का पालन करते हैं।

अमेरिकी सांसद इल्हान उमर ने फिर उगला जहर

भारत नरसंहार के आठवें स्टेज पर पहुंच चुका

● नई दिल्ली

अमेरिका की डेमोक्रेटिक सांसद इल्हान उमर ने भारत को लेकर एक बार फिर विवादित बयान दिया है। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल (आईएएमसी) के एक कार्यक्रम में उन्होंने दावा किया कि भारत नरसंहार के आठवें स्टेज पर पहुंच चुका है। उनका यह बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसे लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। यह कार्यक्रम 7 जून को आयोजित हुआ था, लेकिन इसके वीडियो अब सामने आए हैं।

भारत सरकार ने पहले ही किया था खंडन

केंद्र पहले भी भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के आरोपों को खारिज कर चुकी है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में कहा था कि भारत दुनिया के सबसे सुरक्षित और समावेशी देशों में से एक है, जहां अल्पसंख्यक समुदाय सुरक्षित हैं। जबकि इल्हान ने कहा था कि भारत के पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों को धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।

ब्रिटेन में सबसे पुराने भारतीय-रेस्तरां पर बंद होने का खतरा

वीरास्वामी की 100 साल पुरानी लीज खत्म, अब रेस्तरा मालिक कोर्ट पहुंचे

● लंदन

ब्रिटेन में मौजूद सबसे पुराने भारतीय रेस्तरां वीरास्वामी पर बंद होने का खतरा बढ़ गया है। जिस इमारत में यह रेस्तरां चलता है, उसका मालिक क्राउन एस्टेट है। क्राउन एस्टेट ब्रिटेन की एक बड़ी सरकारी संपत्ति संस्था है, जो राजा या रानी के नाम पर चलती है ।

अब क्राउन एस्टेट वीरास्वामी की इमारत में कुछ बदलाव और नया निर्माण करना चाहते हैं। इसी वजह से उन्होंने रेस्तरां का किराये का समझौता (लीज) आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। वीरास्वामी रेस्तरां की जून 2025 में लीज खत्म हो गई थी। रेस्तरां का कहना है कि अगर लीज नहीं बढ़ाई गई तो उसे 100 साल पुरानी अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। इसलिए रेस्तरां ने इस फैसले को चुनौती देने कोर्ट पहुंचे है। वीरास्वामी की शुरुआत अप्रैल 1926 में हुई थी। यह सिर्फ एक रेस्तरां नहीं बल्कि ब्रिटेन में भारतीय खाने के इतिहास का अहम हिस्सा माना जाता है। पिछले एक सदी में यहां कई मशहूर लोग आ चुके हैं। इनमें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, अभिनेत्री विवियन ली, अभिनेता मार्लन ब्रैंडो, लॉरेंस ओलिवियर, चार्ली चैपलिन और यहां तक कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय भी शामिल हैं। रेस्तरां का मेन्यू भारत में जन्मे एडवर्ड पामर ने तैयार किया था। उन्हें हैदराबाद के शाही महल में बनने वाले व्यंजनों की रेसिपी अपनी दादी से मिली थी और उसी से प्रेरित होकर उन्होंने यहां का खाना तैयार किया।

करी के साथ बीयर पीने की परंपरा यहीं से शुरू हुई

वीरास्वामी को 2016 में मिशेलिन स्टार मिला था। यह दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित रेस्तरां सम्मानों में से एक है। रेस्तरां से जुड़ा एक दिलचस्प दावा भी किया जाता है। कहा जाता है कि इंग्लैंड में करी के साथ बीयर पीने की आदत सबसे पहले इसी रेस्तरां से शुरू हुई थी। रेस्तरां के मालिकों के मुताबिक, डेनमार्क के राजा जब भी लंदन आते थे, तो वीरास्वामी में खाना खाने जरूर पहुंचते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी पसंदीदा कार्ल्सबर्ग बीयर का एक पूरा पीपा रेस्तरां में रखवा दिया था ताकि जब भी वे करी खाने आएं, वही बीयर उन्हें परोसी जा सके। यह रेस्तरां दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन बमबारी (ब्लिट्ज़) से भी बच गया। उसने रेस्तरां उद्योग के उतार-चढ़ाव भी देखे, लेकिन अब एक साल से चल रही कानूनी लड़ाई के बाद उसके अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया है। वीरास्वामी की मूल कंपनी एमडब्ल्यू ईट 29 जून से शुरू होने वाली पांच दिन की सुनवाई में सेंट्रल लंदन काउंटी कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी।

मेलोनी बोलीं, मैंने एक माह से नहीं पी सिगरेट

जी7 समिट में माइक पर रिकॉर्ड हुई बातचीत

● एवियन/ आरएनएन

फ्रांस में चल रहे जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं की अनौपचारिक बातचीत माइक्रोफोन में रिकॉर्ड हो गई। इन नेताओं को सिगरेट, फुटबॉल, तोहफों जैसी बातों पर हल्के-फुल्के मजाक करते हुए सुना गया।

इन सबमें से इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सिगरेट छोड़ देने वाली बातचीत की खूब चर्चा हो रही है।

दरअसल, बैठक शुरू होने से पहले मेलोनी ने नेताओं से बातचीत में कहा कि आज उन्होंने 3 कप कॉफी पी है। यह सुनकर यूरोपीय यूनियन की चीफ उर्सला वॉन डेर लेयेन ने चौंकते हुए पूछा- क्या आज सुबह, उठने के लिए? इस पर जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्त्ज ने मजाक में कहा- और सिगरेट कितनी पी? मेलोनी ने इससे इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने एक महीने से सिगरेट नहीं पी है। यह सुनते ही कनाडा, ब्रिटेन, जापान और यूरोपीय संघ के नेताओं ने उन्हें बधाई दी।

ईयू नेताओं ने उन्हें बधाई दी

सबसे बड़ी खोज : ब्लैक होल के केंद्र में नासा ने खोजा सुपरनोवा का अवशेष

● वाशिंगटन

ब्रह्मांड में ऐसे कई रहस्य हैं, जिनका जवाब दुनियाभर के वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। स्पेस में सबसे रहस्यमयी इलाका 'ब्लैक होल' को माना जाता है। कुछ साल पहले तक ब्लैक होल की बस थ्योरी ही इंसानों के पास थी। लेकिन अब वैज्ञानिकों के पास इसकी तस्वीरें भी हैं।

तमाम वैज्ञानिक और एजेंसियां लगातार ब्लैक होल को और समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी ब्लैक होल के बेहद करीब से ऐसी खबर सामने आई है, जिसने दुनियाभर के खगोलविदों को हैरान कर दिया है। यूएस स्पेस एजेंसी नासा के 'चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी' और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के एक्सएमएम न्यूटन टेलीस्कोप ने मिलकर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के डाउनटाउन यानी बिल्कुल केंद्र में एक अनोखी चीज ढूंढ निकाली है। वैज्ञानिकों को गैलेक्सी के महाविशाल ब्लैक होल, सैजिटेरियस ए (एसजीआर-ए) के बिल्कुल पड़ोस में एक प्राचीन और भयानक तारा विस्फोट (सुपरनोवा) के संभावित अवशेष मिले हैं।

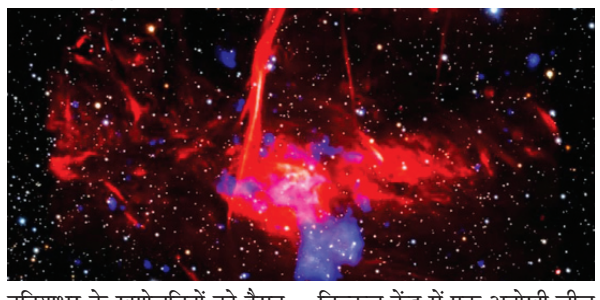

अनंत ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगायी हाजिरी

किया गंगा दर्शन

● वाराणसी

उद्योगपति मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी ने मंगलवार शाम काशी विश्वनाथ मंदिर में विधि-विधान से दर्शन-पूजन किया। गर्भगृह में उन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ का षोडशोपचार विधि से पूजन-अर्चन किया। अनंत अंबानी बाबा विश्वनाथ की सप्तऋषि आरती में भी शामिल हुए।

दर्शन और आरती के बाद उन्होंने मंदिर परिसर का भ्रमण किया।विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के बाद अनंत अंबानी मां अन्नपूर्णा मंदिर पहुंचे। वहां गर्भगृह में 21 ब्राह्मण अर्चकों ने मंत्रोच्चार के साथ मां भगवती का विशेष कुमकुम पूजन संपन्न कराया।उन्होंने मां को माला अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पूजन के उपरांत अनंत अंबानी ने मंदिर के महंत शंकरपुरी जी महाराज से भेंट की।

पाक में सैनिटरी पैड पर 18% टैक्स खत्म किया

इस्लामाबाद, आरएनएन। पाक सरकार सैनिटरी पैड और गर्भनिरोधक प्रोडक्ट्स पर लगने वाला 18 फीसदी सेल्स टैक्स खत्म करने की तैयारी कर रही है।

पिछले हफ्ते पेश किए गए बजट में सरकार ने टैक्स हटाने का प्रस्ताव रखा था। पाक के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने कहा कि सैनिटरी प्रोडक्ट्स महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और सामाजिक जीवन में उनकी भागीदारी के लिए बेहद जरूरी हैं। इसके पीछे उन्होंने देश की तेजी से बढ़ती आबादी को वजह बताया। पाक आबादी के मामले में दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा देश है।

अल नीनो से निपटने का प्लान बनाएं : शिवराज

● नई दिल्ली / आरएनएन

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कृषि भवन, दिल्ली में उच्चस्तरीय साप्ताहिक कृषि समीक्षा बैठक में खरीफ 2026 के लिए देशभर की तैयारियों की बारीकी से समीक्षा की।

संभावित अल नीनो परिस्थितियों के बीच उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दलहन में आत्मनिर्भरता और कम बारिश वाले जिलों के लिए अग्रिम कंटिंजेंसी प्लान पर विशेष जोर देते हुए साफ संदेश दिया कि पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसान हितों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में अल नीनो की संभावित स्थिति पर चर्चा करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ निर्देश दिया कि जिन जिलों में कम बारिश या वर्षा में असमानता की आशंका है, वहां पहले से पूरी तैयारी की जाए।

बैठक में समग्र कृषि क्षेत्र की समीक्षा की गई

आज का इतिहास

- 1576 : अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दीघाटी का युद्ध शुरू हुआ।
- 1758 : फ्रेंच जनरल बुस्सी ने निजाम सलाबत जंग से जाने की इजाजत ली, जो भारत से फ्रांस की मौजूदगी का अंत था।
- 1812 : अमेरिका के राष्ट्रपति जेम्स मेडिसन ने ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।
- 1815 : वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट को हार का सामना करना पड़ा।
- 1858 : झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के निकट लड़ाई के मैदान में ब्रिटिश सेना से लोहा लेने के बाद मारी गई।

बड़ा कदम

कामिकेज ड्रोन के डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से स्वदेशी होगी

स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन डेवलप के लिए टेंडर जारी

● नई दिल्ली

चाहे रूस-यूक्रेन की जंग हो या फिर इजराइल-ईरान के बीच हुआ भीषण युद्ध। इन दोनों जंगों में आत्मघाती यानी कामिकेज ड्रोन का जबरदस्त इस्तेमाल किया गया। ऐसे में अब भारत भी स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन डेवलप करने जा रहा है।

ये प्रोडक्शन भारतीय वायुसेना (आईएएफ) स्वदेशी कंपनियों के साथ मिलकर करेगी। कामिकेज ड्रोन के डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और रखरखाव के लिए पूरी तरह से स्वदेशी इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है।

आईएएफ ने वन-वे अटैक अनमैन्ड एरियल सिस्टम के लिए भारतीय कंपनियों को चुनने के लिए लिमिटेड टेंडर जारी किया है। इस टेंडर में बिना पायलट वाले हवाई सिस्टम के लिए स्वदेशी डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ बनाने और ट्रेनिंग के लिए बोलियांमांगी गई हैं। डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए, इस प्रोजेक्ट को कोयंबटूर के पास सुलूर स्थित 5 बेस रिपेयर डिपो संभालेगा, जिसे नोडल एजेंसी बनाया गया है।

क्या होता है कामिकेज ड्रोन

ओडब्ल्यूए-यूएसए या कामिकेज ड्रोन, ऐसे बिना पायलट वाले हवाई वाहन होते हैं, जो खुद को खत्म करके हमला करते हैं। इसलिए इन्हें आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है। ये टारगेट एरिया तक उड़कर जाते हैं, दुश्मनों का पता लगाते हैं और टकराते ही फट जाते हैं। आईएएफ के पास ड्रोन प्लेटफॉर्म के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (बौद्धिक संपदा अधिकार) रहेंगे। प्रोजेक्ट की शर्त यह है कि ये ड्रोन 16,000 फीट की ऊंचाई तक और दिन-रात, दोनों स्थितियों में काम करने में सक्षम होने चाहिए।

बीसीजी व खसरे के टीकों की कीमत में हुआ इजाफा

केंद्र सरकार ने 21 फीसदी बढ़ोतरी का लिया फैसला
सीरम इंस्टीट्यूट ने की थी कीमत की समीक्षा की अपील

● नई दिल्ली

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की समीक्षा याचिका के बाद, केंद्र ने बीसीजी, खसरा (मिसल्स) और खसरा-रूबेला (एम- आर) वैक्सीन की अधिकतम कीमतों (सीलिंग प्राइस) में लगभग 21 फीसदी की बढ़ोतरी की है।

शा. अधिसूचना में, नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) ने बीसीजी वैक्सीन की अधिकतम कीमत 8.20 रुपए से बढ़ाकर 9.89 रुपए प्रति डोज, खसरे की वैक्सीन की कीमत 51.40 रुपए से बढ़ाकर 62 रुपए प्रति शीशी (वॉयल) और खसरा-रूबेला वैक्सीन की कीमत 72.90 रुपए से बढ़ाकर 87.93 रु. प्रति शीशी कर दी है।

यह बदलाव एनपीपीए के दिसंबर 2024 के उस आदेश के कारण हुआ है, जिसमें ड्रग्स (प्राइसेस कंट्रोल) ऑर्डर, 2013 के तहत एकाधिकार की स्थिति से कीमतों में 17.1 फीसदी की कटौती की थी। इसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट ने समीक्षा की मांग की व तर्क दिया कि वैक्सीन निर्माण प्रक्रिया, तकनीक, चिकित्सीय उपयोग व बाजार की स्थितियों के मामले में आम दवाओं से अलग होती हैं।

हल्दीघाटी विजय के 450 वर्ष पूर्ण होने पर उदयपुर में राष्ट्र चेतना का विराट संगम

महाराणा प्रताप ने धर्म, संस्कृति, स्वाभिमान और राष्ट्रहित के लिए जीवनभर संघर्ष किया - डॉ. मोहन भागवत जी

लोक टुडे

उदयपुर। हल्दीघाटी विजय के 450 वर्ष पूर्ण होने और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती के अवसर पर गांधी ग्राउंड में प्रताप गौरव केन्द्र 'राष्ट्रीय तीर्थ' के तत्वाधान में आयोजित 'राष्ट्र चेतना संकल्प सभा' में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत जी ने कहा कि भारत का इतिहास पराधीनता का नहीं, बल्कि विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध निरंतर चले संघर्ष, प्रतिरोध और आत्मगौरव का इतिहास है। हल्दीघाटी का युद्ध केवल दो सेनाओं का युद्ध नहीं था, बल्कि राष्ट्रचेतना और स्वाभिमान की रक्षा के लिए संपूर्ण समाज द्वारा लड़ा गया महासंग्राम था।

हल्दीघाटी विजय सार्द्ध चतुःशती समारोह में उन्होंने कहा कि युद्ध के उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों, समकालीन स्रोतों और स्वयं मुगल इतिहासकारों के वर्णनों से स्पष्ट होता है कि युद्ध के विभिन्न चरणों में मुगल सेना को पीछे हटना पड़ा। यदि युद्ध के बाद भी शत्रु भय और असुरक्षा की स्थिति में रहा, तो वास्तविक विजय किसकी थी, इसका निर्णय इतिहास स्वयं करता है।

उन्होंने युद्ध के प्रसंगों का उल्लेख करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप की सेना के पहले ही आक्रमण ने मुगल सेना को दूर तक पीछे हटने के लिए विवश कर दिया था। चेतक के अद्भुत पराक्रम, प्रताप की युद्धनीति और सैनिकों के आत्मबल ने सीमित संसाधनों के बावजूद विशाल साम्राज्य की सैन्य शक्ति को चुनौती दी। महाराणा प्रताप की सेना में केवल राजवंश या योद्धा वर्ग नहीं, बल्कि सम्पूर्ण समाज खड़ा था। जाति, पंथ, क्षेत्र और सामाजिक भेदों से ऊपर उठकर समाज राष्ट्ररक्षा के लिए एकजुट हुआ था।

सरसंघचालक जी ने कहा कि भारत का समाज कभी भी स्वेच्छा से पराधीनता स्वीकार करने वाला समाज नहीं रहा। जब-जब विदेशी आक्रांताओं ने इस भूमि पर अधिकार करने का प्रयास किया, तब-तब प्रतिरोध की अग्नि प्रज्ज्वलित हुई। उन्होंने बप्पा रावल, ललितादित्य, महाराणा प्रताप और अन्य वीरों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत की आत्मा को पराजित करना किसी भी आक्रांता के लिए संभव नहीं हो सका।

उन्होंने कहा कि इतिहास को कई बार सत्ता के निकट रहने वालों ने अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया, जिसके कारण अनेक राष्ट्रीय नायकों के योगदान को अपेक्षित स्थान नहीं मिला। हल्दीघाटी के युद्ध के संदर्भ में भी तथ्यों की पुनर्समीक्षा आवश्यक है। जिस महाराणा प्रताप की जयंती आज पूरे देश में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जा रही है, वही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि राष्ट्र अपने वास्तविक नायकों को कभी नहीं भूलता।

'दुनिया में कहीं अकबर की जयंती नहीं मनाई जाती, जबकि महाराणा प्रताप का स्मरण आज भी जन-जन करता है। इतिहास का यह लोकनिर्णय स्वयं बताता है कि विजय किसकी हुई थी।'

उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप को 'हिंदुआ सूरज' यूं ही नहीं कहा गया। उन्होंने अपने धर्म, संस्कृति, स्वाभिमान और राष्ट्रहित के लिए जीवनभर संघर्ष किया। उनका जीवन सत्ता प्राप्ति का नहीं, बल्कि लोककल्याण, आदर्श शासन और राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा का उदाहरण है। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा आदर्श स्थापित किया जो आज भी राष्ट्र जीवन को प्रेरणा देता है।

सरसंघचालक ने कहा कि भारत की शक्ति उसकी एकता, समरसता और आत्मविश्वास में निहित है। केवल संकट के समय ही नहीं, बल्कि सामान्य परिस्थितियों में भी समाज को संगठित और जागृत रहना होगा। स्वाभिमान और 'स्व' का भाव जब तक जीवित रहेगा, तब तक भारत हर चुनौती का सामना करते हुए विजय की नई गाथाएं रचता रहेगा। सभी नागरिक महाराणा प्रताप के जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्रोत्थान, समाज संगठन और विश्वकल्याण का संकल्प लें। भारत का उत्थान ही विश्व के कल्याण का मार्ग है और इसी दिशा में कार्य करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है।

हल्दीघाटी विजय का गौरव इतिहास की भ्रांतियों का करेगा अंत - श्रीजी श्याम शरण

समारोह में विशिष्ट अतिथि निम्बार्काचार्य श्रीजी श्याम शरण देवाचार्य जी ने कहा कि यह आयोजन केवल एक ऐतिहासिक स्मरण नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति, स्वाभिमान और सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का महापर्व है। वर्षों से इतिहास के संबंध में फैलाई गई भ्रांतियों का निराकरण अब समाज के सामने हो रहा है और महाराणा प्रताप के वास्तविक गौरव को पुनः स्थापित किया जा रहा है। मेवाड़ की भूमि शौर्य और भक्ति दोनों की पावन धरा है। एक ओर इस भूमि ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जैसे राष्ट्रनायक को जन्म दिया, वहीं दूसरी ओर भक्तिमती मीराबाई जैसी महान कृष्णभक्त को भी दुनिया को दिया। जब मातृभूमि और सनातन संस्कृति पर संकट आया, तब महाराणा प्रताप ने भगवान श्रीराम के 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' के आदर्श को आत्मसात करते हुए अपना सर्वस्व राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। श्रीजी श्याम शरण जी ने कहा कि राष्ट्रभक्ति की यही चेतना समय-समय पर विभिन्न रूपों में प्रकट होती रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रत्येक स्वयंसेवक 'नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे' की भावना के साथ मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने समाज से जाति, वर्ग और संकीर्णताओं से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत की सनातन संस्कृति 'वसुधैव कुटुम्बकम्' और 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' का संदेश देती है।

हल्दीघाटी विजय का सत्य जन-जन तक पहुंचाना होगा - डॉ. भगवती प्रकाश शर्मा

समारोह की अध्यक्षता करते हुए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति के अध्यक्ष डॉ. भगवती प्रकाश शर्मा जी ने कहा कि अब समय आ गया है कि हल्दीघाटी युद्ध के वास्तविक इतिहास को जन-जन तक पहुंचाया जाए और उन भ्रांतियों का निराकरण किया जाए जो वर्षों से समाज में प्रचारित की जाती रही हैं। इस वर्ष महाराणा प्रताप जयंती और हल्दीघाटी युद्ध के 450 वर्ष पूर्ण होने का दुर्लभ संयोग बना है, जिससे इस आयोजन का महत्व और बढ़ गया है। उपलब्ध ऐतिहासिक प्रमाण स्पष्ट करते हैं कि हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को परास्त कर स्वाधीनता, स्वाभिमान और राष्ट्रधर्म की रक्षा का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा कि हल्दीघाटी का युद्ध केवल दो सेनाओं के बीच संघर्ष नहीं था, बल्कि विदेशी साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध भारतीय अस्मिता की रक्षा का महान अभियान था। मेवाड़ ने कभी भी विदेशी सत्ता के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया और अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखा। समाज के सभी वर्ग अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर हल्दीघाटी विजय के ऐतिहासिक सत्य को नई पीढ़ी तक पहुंचाएं। उन्होंने आयोजन को सफल बनाने में प्रशासन, मीडिया, सामाजिक संगठनों एवं हजारों कार्यकर्ताओं के योगदान की सराहना करते हुए इसे राष्ट्रचेतना के नवजागरण का ऐतिहासिक अभियान बताया। प्रताप गौरव केन्द्र के निदेशक अनुराग सक्सेना ने सभी का स्वागत करते हुए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति व समिति के अंतर्गत संचालित प्रताप गौरव केन्द्र का परिचय दिया। प्रताप गौरव केंद्र में श्रव्य दृश्य प्रदर्शनी से महाराणा प्रताप के हल्दीघाटी युद्ध में हार होने के विमर्श को तोड़ा गया है और महाराणा प्रताप के हल्दीघाटी युद्ध में विजय होने के विमर्श को स्थापित किया गया है। हल्दीघाटी विजय सार्द्ध चतुः शती समारोह के तहत वर्ष भर हुए आयोजनों की जानकारी भी दी। राष्ट्र चेतना संकल्प सभा में मेवाड़-वागड़ के कई संत-महंतों का सान्निध्य प्राप्त हुआ। मेवाड़ राजपरिवार के महाराणा विश्वराज सिंह मेवाड़ भी उपस्थित रहे।

सेवा शिविरों से लोगों की समस्याओं का हर हाल में हो समाधान, अधिकारी नहीं बरतें कोई कोताही: मुख्यमंत्री

लाभार्थियों को पट्टे, प्रमाण पत्र, सहायता राशि के चेक एवं सहायक उपकरण किए वितरित

लोक टुडे

उदयपुर/जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को उदयपुर में शहरी सेवा शिविर का अवलोकन कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने उदयपुर विकास प्राधिकरण परिसर में आयोजित शिविर में उपस्थित लाभार्थियों से संवाद कर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं शिविर के संबंध में फीडबैक लिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं एवं सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाना है। इसी उद्देश्य से प्रदेशभर में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित हो।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सेवा शिविरों के माध्यम से पट्टा वितरण, नामांतरण, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र सहित विभिन्न राजस्व एवं नागरिक सुविधाओं से जुड़े प्रकरणों का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आवश्यक जांच अथवा प्रक्रिया के कारण अतिरिक्त समय लगने वाले प्रकरणों के निस्तारण के लिए फॉलोअप शिविर भी आयोजित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिविरों में आमजन से जुड़े छोटे से लेकर बड़े कार्यों को भी गंभीरता से लिया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिविरों में आमजन की समस्याओं का समाधान हर हाल में किया जाए तथा इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, महिलाओं और वंचित वर्गों सहित सभी वर्गों को मूलभूत सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध हों। पार्क, सड़क, नाली, सीवरेज, बिजली तथा अन्य नगरीय सुविधाओं से संबंधित समस्याओं का भी प्राथमिकता से समाधान किया जाए।

मुख्यमंत्री ने आमजन से आह्वान किया कि वे अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों को शिविरों तक पहुंचाने में सहयोग करें, ताकि पात्र व्यक्ति योजनाओं और सेवाओं का लाभ सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों की सामूहिक भागीदारी से ही इन शिविरों की सार्थकता सुनिश्चित होगी।

मुख्यमंत्री ने शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉल्स का अवलोकन करते हुए जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को पट्टे, प्रमाण पत्र, भवन निर्माण स्वीकृति एवं सहायता राशि के चेक तथा दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण भी प्रदान किए। लाभार्थियों ने राज्य सरकार की जनकल्याणकारी पहल के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, विधायक ताराचंद जैन, फूल सिंह मीणा, उदयलाल डांगी, श्रीचंद कृपलानी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण एवं आमजन उपस्थित रहे।

क्या फिर जयपुर बनेगा 'जलपुर'?

प्री-मानसून बारिश के बाद निगम की तैयारियां

प्रमोद कुमार

जयपुर में मानसून की आधिकारिक एंट्री से पहले हुई प्री-मानसून बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी है। शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनने से लोगों को एक बार फिर उन दिनों की याद आ गई, जब बारिश के दौरान जयपुर को 'जलपुर' कहा जाने लगा था। सड़कों पर भरे पानी, यातायात अव्यवस्था और लोगों की परेशानी ने निगम के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि नगर निगम का कहना है कि इस बार मानसून से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। निगम ने शहर के सात जोनों में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं, जो 15 जून से मानसून समाप्त होने तक 24 घंटे कार्यरत रहेंगे। इन नियंत्रण कक्षों के माध्यम से जलभराव, नालों की सफाई और अन्य आपात स्थितियों की निगरानी की जाएगी।

बारिश का इंतजार, निगम की टीम तैयार:

आपदा प्रबंधन को लेकर निगम ने विशेष इंतजाम करने का दावा किया है। प्रत्येक नियंत्रण कक्ष पर करीब 15 हजार मिट्टी के कट्टे उपलब्ध रखे गए हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर-ट्रॉली, मड पंप, लाइफ जैकेट, नाव और अन्य आवश्यक उपकरण भी तैनात किए गए हैं, ताकि जलभराव या बाढ़ जैसी स्थिति में तत्काल राहत कार्य शुरू किया जा सके। अधिशासी अभियंता नीरज मीणा के अनुसार किसी भी क्षेत्र से शिकायत मिलने पर संबंधित टीम तुरंत मौके पर पहुंचेगी। वहीं अति आयुक्त नरेंद्र बंसल ने मानसून के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सभी जोन कार्यालयों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी तय कर दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये तैयारियां जमीनी स्तर पर असरदार साबित होंगी? क्योंकि पिछले कई वर्षों से जयपुर के लोग बारिश के दौरान जलभराव, ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था की समस्या झेलते आ रहे हैं। कई इलाकों में थोड़ी देर की बारिश भी लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है।

निगम ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर:

मानसरोवर- 0141-2395566
मालवीय नगर- 0141-2755930
विश्वकर्मा फायर स्टेशन- 0141-2330080
खिरनी फाटक- 0141-8764880018
घाटगेट- 0141-261550
आमेर- 0141-2531282
कांवटिया सर्किल- 0141-2203518

इसके अलावा तैयारी:

ट्रैक्टर-ट्रॉली
मड पंप
लाइफ जैकेट
नाव

आज 29 जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी:तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे

जयपुर

राजस्थान में बैक-टू-बैक वेदर सिस्टम आने से प्री-मानसून की बारिश का दौर जारी है। गुरुवार को एक नया वेदर सिस्टम राज्य में एक्टिव होगा। जिसके असर से अगले तीन दिनों तक राज्य के दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में आंधी-बारिश होगी। मौसम विभाग ने 21 जून तक प्रदेश में इस सिस्टम का असर रहने का अनुमान जताया है।

लगातार बदल रहे मौसम के कारण दिन का तापमान भी 40 डिग्री से कम हो गया है। आज प्रदेश के 29 जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी है।

वहीं, पिछले 24 घंटे में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, करौली और इनके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हुई। राजस्थान में 25 जून बाद मानसून आने की संभावना है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक संपादक: नीरज मेहरा द्वारा बोनस ग्राफिक्स, लक्ष्मी नगर, झोटवाड़ा मार्ग, अजमेर रोड़, जयपुर-302006 से मुद्रित एवं 141, दयानन्द नगर, फेज प्रथम झालाना डूंगरी गली नंबर 19, थाना गांधी नगर, जयपुर (राज.) से प्रकाशित। प्रबंध संपादक- पी.के.बृजवाल, 9950325930, 9571635930 (कानूनी सलाहकार एडवोकेट कैलाशनाथ भट्ट)